सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 9 ● अंक: 179 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023
मूल्य ₹ 3/-

फिर चूकीं सिंधू, ऑस्ट्रेलियन ओपन... 7

राजस्थान का रण: गहलोत को दिखानों... 3

बसपा की एक सोच समतामूलक... 2

तकनीक बस एक साधन है। बच्चों को एक साथ काम करने और मोटिवेट करने के लिए, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण हैं।

-बिल गेट्स

राहुल गांधी को सुप्रीम राहत कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला पलटा

» सांसदी बहाल, फिर जा सकेंगे संसद

» कांग्रेस बोली सच्चाई की जीत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। एससी ने मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसी के साथ उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी। इस फैसले से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं कांग्रेस नताओं ने कहा है कि ये सच्चाई की जीत है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते-जय हिंद।

इससे पहले जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर सांसद अयोग्य नहीं करार दिया जाता। एससी में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क रखे। राहुल की याचिका पीठ ने सुनी। अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।

सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही : जस्टिस गवई

किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना क्या सजा पर रोक का कोई आधार नहीं है? जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को चुनता है तो क्या वो क्षेत्र बिना उसके सांसद को उपस्थिति का रहना ठीक है ?

जब इस तरह के मामले में अधिकतम सजा दो साल दी गई है? जस्टिस गवई ने कहा कि क्या यह एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि जो निर्वाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को चुनता है वह गैर-प्रतिनिधित्व वाला हो जाएगा? ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है,

जब आप अधिकतम सज़ा देते हैं तो आप कुछ तर्क देते हैं कि अधिकतम सज़ा क्यों दी जानी चाहिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई फुसफुसाहट नहीं, कोर्ट ने कहा कि आप न केवल एक व्यक्ति के अधिकार का बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। केवल वह सांसद हैं, यह सजा निलंबित करने का आधार नहीं हो सकता, लेकिन क्या उन्होंने दूसरे हिस्से को भी छुआ है? हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना बहुत दिलचस्प है, इस फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए।

“तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं है। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते।

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था।

केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं : सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि मोदी सरनेम और अन्य से संबंधित प्रत्येक मामला भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है,इसके पीछे एक प्रेरित पैटर्न दिखाता है,राहुल गांधी इन सभी मामलों में केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं है, जैसा कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है, दिलचस्प बात यह है कि 13 करोड़ की आबाद वाले इस छोटे समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं, उनमें से केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं, क्या ये बहुत अजीब नहीं है, उस 13 करोड़ की आबादी में न कोई एकरूपता है, न पहचान की एकरूपता है, न कोई सीमा रेखा है।

भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया : जेठमलानी

इस मामले में सिंघवी के बाद पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने बहस शुरू की। महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि सिंघवी ने भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में ढेर सारे सबूत मौजूद हैं, माना कि वह मौजूद नहीं थे लेकिन उन्होंने इसे यूट्यूब पर देखा और पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने महेश जेठमलानी से पूछा कि स्पीच के कुछ वाक्य मिसिंग थे, कुल 50 मिनट का भाषण है, इसकी तीन सीडी पेश की गई थी, दूसरी सीडी में सूबत हैं। स्पीच को पूरे देश ने सुना है, राहुल गांधी की स्पीच के बारे में अदालत में बताया भी गया है, राहुल गांधी का इरादा मोदी सरनेम वाले लोगों को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि पीएम भी यही सरनेम लगाते हैं।

“मा. सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए।

अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

“राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।

अशोक गहलोत, सीएम राजस्थान

“घिनौनी साजिश नाकाम.. राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए थे.. आज खुशी का दिन है...मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा।

अधीर रंजन चौधरी, नेता सदन, कांग्रेस

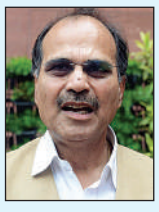

भाजपा का 2024 में जाना तय

» पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा- मोदी-योगी सरकार की सच्चाई लोग जान गए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लाख कोशिश कर ले लेकिन 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर जाना ही है। कहा कि भाजपा ने जो झूठे सपने दिखाए थे उनकी सच्चाई लोग जान गए हैं। अब सब्र का बांध टूट रहा है। सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि जबसे पीडीए की चर्चा आई है, भाजपा में घबराहट बढ़ गई है। समाज का हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आक्रोशित है।

उन्होंने कहा कि षड्यंत्र करके समाजवादियों को सरकार में नहीं आने दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार धांधली रोकेगी। बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। आजमी ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की पहली कोशिश तब हुई, जब श्रद्धा की हत्या हुई। हत्यारे का नाम आफताब था, लेकिन जब जांच की गई, तो पता चला कि आफताब मुस्लिम नहीं, पारसी था। इसके बाद फिरकापरस्तों के एजेंडे और प्रोपेगेंडा को झटका लगा। अबू आसिम ने कहा कि देश के बंटवारे में हम जैसे लोगों ने अपना देश चुना। चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों से विनती की और मुसलमानों ने भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार कर लिया। लाखों लोगों को बुलाया गया, लेकिन मुसलमानों ने वतन अजीज को चुना। आज़मी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथी को एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने गिरफ्तार कर लिया। वकील रोहिणी सालियान ने उन पर मामले को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें मामले को ठंडे दिमाग से संभालने के लिए कहा गया था, बाद में वह मामले से हट गईं। एटीएस के गवाहों को गुमराह किया जा रहा है।

लोगों के सब्र का बांध टूटा

मुस्लिमों को बदनाम करने की हो रही साजिश : अबु आसिम आजमी

हेट स्पीच के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आजाद मैदान पर आंदोलन किया गया। इस मौके पर सपा विधायक अबू आसिम आज़मी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में फिरकापरस्ती बढ़ती जा रही है। यह फिरकापरस्त पार्टियां हैं, जो आक्रोश रैली निकालकर और मोटरसाइकलों पर झंडा लगाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। देशभक्ति और देशभक्ति का सबूत मांगने वाले मुसलमानों ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

मेयर के दौरे की फाइल सीधे भेजने पर एलजी ने जताई नाराजगी

» कहा- इस मामले का राजनीतिकरण न हो

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी फाइल दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर सीधे भेजने पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव स्थानांतरित विषयों पर आधिकारिक फाइलें दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे एलजी कार्यालय को भेज रहे हैं। मेयर शैली ओबेरॉय को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट-2023 में भाग लेने की अनुमति देने के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

आयुक्त ने फाइल को शहरी विकास सचिव संजय गोयल को भेजा और उन्होंने इसे मुख्य सचिव नरेश कुमार के पास भेज दिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने फाइल सीधे एलजी के पास भेज दी। बताया जा रहा है कि एलजी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया है कि फाइल उचित माध्यम से भेजी जाए। हालांकि, एलजी कार्यालय की ओर से मामले का राजनीतिकरण करने पर भी नाराजगी जाहिर की गई है।

देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा इंडिया

» ममता ने कहा- लोस चुनाव में जीत के लिए ईवीएम में भाजपा करेगी धांधली

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस बात के सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के अपने प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया 2024 का चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इंडिया देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पहले से ही योजना बना रहे हैं। वे ईवीएम को हैक

करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इस बारे में सुना है व सबूत हासिल किए हैं तथा और अधिक सबूत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बना गठबंधन अपनी अगली बैठक में इस पर चर्चा करेगा। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई मूल्य नहीं है, जबकि इंडिया का अस्तित्व पूरे देश में है।

लोगों को बताएंगे भाजपा की साजिश: आलम

» बोले-इस सरकार में अंबेडकर को अपमानित करने वालों का हो रहा सम्मान

» कांग्रेस शुरू करेगी जय जवाहर-जय भीम कार्यक्रम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष ने शाहनवाज आलम कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस कमेटी नए सिरे से ने दलित- मुस्लिम गठजोड़ बनाने में जुटेगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने जय जवाहर- जय भीम कार्यक्रम शुरू किया है। अल्पसंख्यक नेता दलितों को एक तस्वीर भेंट करेंगे। इस तस्वीर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू व अन्य नेताओं को डा. भीमराम अंबेडकर संविधान की प्रति देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि अभियान के दौरान दलितों को यह समझाया जाएगा कि दलित- मुस्लिम एकजुटता का अभाव होने

के बाद सत्तासीन भाजपा सरकार लगातार दलितों को उपेक्षित कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। यूनिफार्म सिविल कोड के बहाने भविष्य में आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में उसके साथ दलित और अल्पसंख्यक वोटबैंक दोबारा एकजुट हो जाए तो वह सियासी वैतरणी पार कर सकती है। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलेवार दौरा करके पुराने दलित एवं अल्पसंख्यक नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उनसे मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे हैं। विभिन्नन दलों में उपेक्षित पड़े दलित एवं अल्पसंख्यक नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत पिछले दिनों दलित बस्तियों में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के नीति निर्धारकों का मामना है कि यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद तमाम दलित एवं अल्पसंख्यक नेताओं ने कांग्रेस का रूख किया है। अब इसी तर्ज पर जय जवाहर-जय भीम कार्यक्रम तय किया गया।

5.50 लाख दलित परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य

अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि इस अभियान के जरिए 5.50 लाख दलित परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हर दिन हर जिले में 100 दलित परिवारों में तस्वीर बांटी जाएगी। विभिन्नन स्थानों पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा। यदि दलित व मुस्लिम एकजुट हो गए तो करीब 40 फीसदी वोटबैंक कांग्रेस के पद में होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे, प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह, मोहम्मद शमीम खान, डॉ शहजाद आलम, खालिद मोहम्मद खान आदि मौजूद रहे।

बसपा की एक सोच समतामूलक समाज की स्थापना करना : आकाश

» भाजपा से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भाजपा से बसपा किसी तरह का गठबंधन नहीं करने जा रही है। इस तरह की संभावनाओं को बसपा प्रमुख के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने खारिज किया है। उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि गठबंधन को लेकर बसपा का स्टैंड बिल्कुल साफ है। इसके साथ ही उन्होंने तीसरे विकल्प की बात कर नई चर्चा छेड़ दी है।

उन्होंने कहा है कि बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आकाश की यह प्रतिक्रिया उन खबरों को लेकर आई है, जिनमें कहा जा रहा है कि सपा और आरएलडी का सफाया करने के लिए भाजपा बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। आकाश ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। इसकी एक ही सोच है, समतामूलक समाज की स्थापना करना।

मायावती के नेतृत्व में बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे हताश हमारे विरोधी साम-दाम-दंड-भेद की नीति का इस्तेमाल कर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हम सभी को इससे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मायावती का पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गठबंधन से साफ इनकार किया है। वहीं कुछ खबरें शेयर की हैं, जिनमें भाजपा और बसपा गठबंधन की बात कही गई है।

तीसरा विकल्प बनेगी बसपा

भाजपा से गठबंधन को लेकर सफाई के साथ ही आकाश ने तीसरे विकल्प की बात छेड़कर नई चर्चाओं को हवा दे दी है। अब चर्चा यह है कि बसपा तीसरा विकल्प कैसे बनेगी? इसमें मायावती के गठबंधन को लेकर बदलते रुख पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया। उसके बाद चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं की बात कही। वहीं, हरियाणा और पंजाब में चुनाव पूर्व गठबंधन का रास्ता साफ रखा है। इधर, एआईएमआईएम और महान दल जैसे छोटे दलों से अंदरखाने चुनावी तालमेल की चर्चाएं भी हो रही हैं। इस तरह बसपा की कोशिश हो सकती है कि भाजपा और संयुक्त विपक्ष से अलग कुछ छोटे दलों से तालमेल करके अगर कुछ सीटें आ जाती हैं तो फिर चुनाव बाद संभावनाएं बन सकती हैं। अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वह उसमें अपनी जगह बना सकती है। इससे मायावती के बैलेंस ऑफ पावर बनने के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है।

राजस्थान का रण: गहलोत को दिखाना होगा दम

भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई

- मोदी-समेत कई दिग्गज राज्य को मथेंगे
- विधान सभा चुनाव होगा मोदी बनाम गहलोत
- कांग्रेस को रहना होगा सर्तक, गुटबाजी को रोकना जरूरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस में तैयारी जोरों पर जारी है। जहां बीजेपी अपने बड़े नेताओं को वहां के सियासी संग्राम में उतार चुकी है वहीं अशोक गहलोत अकेले ही मोर्चा संभाल रहे हैं। पीएम मोदी के आरोपों से लेकर हरियाणा के सीएम के दलीलों को अकेले ही जवाबी हमले से खारिज कर रहे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राजस्थान में गहलोत अकेले ही भाजपा की मोदी मंडली को राज्य में चारों खानें चित करने की तैयारी में जुटें हैं। हालांकि उनके दल के अन्य नेता भी उनका हर कदम पर साथ दे रहे परंतु राज्य की जिम्मेदारी उन्हीं पर है इसलिए जवाबदेही भी उन्हीं की है। राजस्थान में अब तक भाजपा ने पीएम नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है।

अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष चार नेताओं को चार प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी है। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे-सभाएं कर चुके मोदी ने अब प्रदेश के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया है। इनमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की मानें तो इसके बाद विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर वे फीडबैक लेंगे। मोदी जब राजस्थान के 24 लोकसभा और चार राज्यसभा सांसदों के साथ बातचीत करेंगे तो उसमें चार केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी शामिल होंगे। चार महीने पहले सभी सांसदों को मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब तक किसने क्या किया, इसका ब्यौरा लिया जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों-योजनाओं, गहलोत, मंत्रियों, विधायकों की आलोचना के लिए कौन-कौन से बिंदुओं पर वैचारिक, मौखिक और राजनीतिक आक्रमण किया जाना चाहिए। टिकट वितरण पर भी मोदी की कोर टीम ही फैसले करेगी। सूत्रों के अनुसार विधायकों की पहली मीटिंग 25-26 अगस्त के आसपास हो सकती है। राजस्थान में पिछले दो दशक में वर्ष 2002 से 2018 तक चार चुनावों (2003, 2008, 2013 और 2018) में वसुंधरा राजे ही सीएम फेस भी रहीं। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति तय हुई। पिछले चुनावों में 2018 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, तो खुद शाह, वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के हिसाब से रणनीति तय होती थी।

धार्मिक स्थलों पर रहेगी नजर

राजस्थान में भाजपा तीन बड़े धार्मिक स्थलों से जनसमर्थन रैलियां निकालने वाली है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इन धार्मिक स्थानों से निकलने वाली रैलियों का नेतृत्व कौनसा नेता करेगा। इसका निर्णय भी क्रूमोदी और उनकी कोर टीम ही करेगी। यह रैलियां रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेशजी, लोकदेवता गोगाजी की गोगामेढ़ी स्थली (हनुमानगढ़) और आदिवासियों के तीर्थस्थल बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) से निकाली जाएंगी। इन जनसमर्थन रैलियों के नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और राज्य सभा सांसद डॉ. किरोणी लाल मीणा आदि के नामों पर विचार किया जा रहा है। मोदी के साथ अर्जुनराम मेघवाल और प्रहलाद जोशी। दोनों मंत्रियों के पास राजस्थान से जुड़ी खास जिम्मेदारियां हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है।

फीडबैक देने वाली कोर टीम तैयार

राजस्थान विधानसभा चुनाव पर फोकस बढ़ाने के लिए क्रूमोदी की कोर टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने हाल ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले संसद के साथी सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष भी नियुक्त कर चुके हैं। वहीं, मोदी की धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों की रणनीति को अमली जामा पहनाने वाले केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का भी पॉलिटिकल प्रमोशन किया है। प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी और मेघवाल तीनों ही संसद के साथी हैं। ऐसे में तीनों की ट्यूनिंग मोदी की टीम के हिसाब से पहले ही सेट है।

जल्द होंगी पीएम की और सभाएं- सीपी जोशी

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भास्कर को बताया कि राजस्थान को लेकर पीएम मोदी की विशेष रणनीति है। राजस्थान में बढ़ते दुष्कर्म, बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों पर मोदी के ट्वीट करने से निस्संदेह हमारे प्रयासों और आंदोलन को बल मिला है। उनके ट्वीट के आह्वान पर हजारों लोगों ने सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस केवल चुनाव आने पर योजनाएं लॉन्च करती हैं, जबकि क्रूमोदी ने पूरे नौ साल में देश का कायाकल्प किया है। उन्होंने राजस्थान को हाल ही में कई हाईवे, वंदे भारत ट्रेन, कई मेडिकल कॉलेज, उज्जवला गैस, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ दिया है। वे राजस्थान के साथ इन सब योजनाओं को साझा कर रहे हैं।

कांग्रेस की बढ़ती ताकत से घबराई भाजपा

पिछले साढ़े चार साल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। एक समय था जब कांग्रेस देश में केवल दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सत्ता में रह गई थी। राजस्थान में दो बार बगावत का खेल भी हुआ, लेकिन सरकार नहीं गिरी। इससे कांग्रेस को ताकत हासिल हुई। इसके बाद कांग्रेस दोबारा खड़ी हुई। हिमाचल-कर्नाटक जैसे राज्यों में जीत दर्ज की। अब इस ताकत को खत्म करना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है।भाजपा ने वर्ष 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें कांग्रेस से छीन ली थीं। हालांकि, 2019 के चुनाव में एक सीट नागौर गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल को दी गई। 2019 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित चार बड़े केन्द्रीय मंत्रियों और स्थानीय स्तर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को ष्टरूफेस के लिए रेस में माना जाता है। अशोक गहलोत और कांग्रेस इसे लेकर कई बार राजनीतिक कटाक्ष भी करते रहे हैं।

राजस्थान में गहलोत अकेले ही भाजपा की मोदी मंडली को राज्य में चारों खानें चित करने की तैयारी में जुटें हैं।

राजस्थान की सियासत पर नूहं हिसा का असर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने हरियाणा समकक्ष मनोहर लाल खट्टर पर नूंह हिंसा पर असहयोग करने का आरोप लगाया। हरियाणा के सीएम ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि राजस्थान सरकार को नूंह हिंसा में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। 31 जुलाई को नूंह में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क गई और कारों में आग लगा दी गई। हरियाणा के सीएम ने बुधवार को अशोक गहलोत से बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर का नाम लिए बिना उन्हें गिरफ्तार करने का आग्रह किया था, जो कथित तौर पर नूंह हिंसा में शामिल है और राजस्थान से भाग गया है। खट्टर के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, गहलोत ने उन पर असहयोग का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा, कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि वह राजस्थान पुलिस की हरसंभव मदद करेंगे, लेकिन जब हमारी पुलिस नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई। हरियाणा पुलिस ने सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस फरार आरोपियों को ढूंढने में राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में विफल रहे और अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जो उचित नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि राज्य को बजरंग दल नेता मोनू मानेसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने ही सोमवार की हिंसा के लिए लोगों को उकसाया था जिससे राज्य भर में सांप्रदायिक झड़पें हुईं और छह लोगों की जान चली गई। मोनू मानेसर के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है, हरियाणा सरकार इस मामले में राजस्थान पुलिस का सहयोग करेगी। अपने बयान में खट्टर ने कहा कि मैंने राजस्थान सरकार से कहा है कि अगर उन्हें उसका पता लगाने के लिए मदद की जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बढ़ाना उचित कदम

ऑनलाइन गेमिंग पर भारी-भरकम टैक्स लगाने का फैसला सरकार ने किया है। यह एक उम्दा फैसला है। आम जन ने स्वागत किया है पर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। गेमिंग से कमाई पर सरकार उपयोग कर्ता से चार्ज वसूलेगी। ये फैसला छोटे बच्चों के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि जब इन पर टैक्स लगेगा तो यह सारे एप जो इन गेमों को मुहैया करवाते महंगे हो जाएंगे ऐसे में बच्चों को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसे में महंगे होने के कारण बहुत से बच्चे व उनके माता-पिता इन गेंमों से बच्चों को दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। गौरतलब हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को शामिल माना गया है जो इस तरह की टैक्स लागू करने के पक्ष में थे। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ी है और यूजर्स के लिए इसका स्कोप भी काफी बड़ा है।

> गौरतलब हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को शामिल माना गया है जो इस तरह की टैक्स लागू करने के पक्ष में थे। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ी है और यूजर्स के लिए इसका स्कोप भी काफी बड़ा है।

ये हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही है। इस बार जो खबर आ रही है वो इस इंडस्ट्री को झटका दे सकती है। इस बैठक में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर 28 फीसद की जीएसटी लगाई जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि इसे लागू करने के लिए आवश्यक कर कानून में बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाना था। हालांकि, दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया था वहीं, गोवा और सिक्किम जीजीआर (सकल गेमिंग रेवन्यू) पर कर लगाना चाहते थे लेकिन सट्टेबाजी पर नहीं। वित्त मंत्री ने ने कहा कि कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश तक अन्य राज्य चाहते हैं कि जो फैसला पिछली बैठक में लिया गया था उसे लागू किया जाए। साथ ही कहा है कि केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक बदलाव के बाद नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा और 6 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने भारत में उस फंड पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया था जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अपने ग्राहकों से लेती हैं। इस फैसले से इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा था। भारत की गेमिंग मार्केट 2025 तक 5 बिलियन डॉलर की हो जाएगी जो 2022 में 2.8 बिलियन डॉलर की है। इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 28 से 30 फीसद तक है। भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2023 तक 500 मिलियन हो सकती है जो 2022 में 420 मिलियन थी। भारत में तेजी से यह गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। इसके बढ़ने से बच्चे भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी वजह से इन गेमिंग एप से होने वाले साइड इफेक्ट भी आज के बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं ऐसे में टैक्स बढ़ने से इन गेमों के महंगे होने के आसर हैं और हो सकता है दाम पढ़ने का असर बच्चों की आर्थिकी पर पड़ेगी ऐसे में वह इससे दूसरे होंगे।

संजय

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

कर्ज वसूली नीति में विसंगति के यक्ष प्रश्न

देविंदर शर्मा

कुछेक साल पहले की बात है, हरियाणा का एक किसान भूमिगत पाइप के लिए उधार लिए गए छह लाख रुपये नहीं चुका सका। इस पर स्थानीय अदालत ने उसे दो साल के लिए जेल भेज दिया। इसके अलावा उस पर अतिरिक्त 9.83 लाख रुपये जुर्माना भी लगा दिया गया। केवल हरियाणा में ही नहीं, बल्कि हाल के सालों में देशभर में ऐसे सैकड़ों किसान पैसा न चुका पाने के चलते सलाखों के पीछे पहुंचाए गये, जिनकी ओर बैंकों की मामूली राशि ही बकाया थी। यदि जेल भी न भेजे गये, तो ऐसे किसानों की बड़ी संख्या है जिनकी जमीन कुर्क करने से पूर्व बैंक उनके ट्रैक्टर व अन्य अचल संपदा को जब्त करते रहे हैं। आमतौर पर फसल नष्ट होने या फिर रेट गिर जाने की वजह से किस्तों का भुगतान न कर सकने वाले इन छोटी अवधि के बकायेदारों के बचाव में आने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी, धोखा करने वाले और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले अमीरों को रक्षा कवच प्रदान किया है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार कर आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे खाते में डालने की अनुमति राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी है। बारह महीने की 'कूलिंग अवधि' के बाद, ये डिफॉल्टर, जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है लेकिन पैसा लौटाने से इनकार करते हैं, नये लोन प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई कहता है, यदि यह समाधान का एक वैध तंत्र है तो पहले इसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये कि क्यों किसी विरले मामले में ही यह समाधान एमएसएमई सेक्टर और किसानों पर लागू होता है, या फिर उस मध्यम वर्ग पर भी कभी-कभार ही क्यों लागू हुआ हो जो टैक्स देने के बाद बची अपनी मेहनत की कमाई से कार लोन या गृह ऋण लेते हैं। इसके अलावा कोई कारण नहीं बनता कि क्यों बैंकों, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनांस संस्थाओं द्वारा रखे गये भाड़े के लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ लोगों की अचल संपत्तियां जब्त करने के लिए नियमित तौर पर कड़े और अशिष्ट हथकंडे अपनाते हैं।

हाल ही के एक मामले में एक ऋण डिफाल्टर से रिकवरी एजेंटों द्वारा टोल बैरियर पर ही कार जब्त कर ली गयी। इसी तरह एक अन्य मामले में झारखंड में कर्ज न चुका पाने वाले एक किसान की गर्भवती बेटी की मौत के लिए एक नॉन बैंक वित्तीय कंपनी के प्रमुख ने क्षमा मांगी है। उस लड़की को

रिकवरी एजेंटों ने उस वक्त कुचल डाला था जब वे उसके किसान पिता का लोन पर लिया गया ट्रैक्टर लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे। आरबीआई ने इस ओर से नजरें फेर ली थीं। असल में सबसे पहले तो आरबीआई के उस विवादास्पद सर्कुलर से बेहद हैरान हूं, जिसने बैंकों को जानबूझकर ऐसे डिफाल्टर्स के साथ समझौता निपटान करने की अनुमति दी, जिन्हें वास्तव में अब तक जेल में होना चाहिए था। दूसरे, इस सर्कुलर के बारे में मुद्दा उछलने के बाद जारी किए गए सतही स्पष्टीकरण से जवाब मिलने के बजाय और अधिक सवाल खड़े हो गए हैं। आरबीआई की उदारता केवल अमीर डिफॉल्टरों के लिए है, जो यूं भी बैंकिंग नियामक द्वारा तय नियमों-विनियमों की कोई खास परवाह नहीं करते हैं। अन्यथा कैसे और क्यों जानबूझकर डिफाल्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो बीते दो सालों में 41 फीसदी तक बढ़ चुकी है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 16,044 हो गई है- जिन पर बैंकों का सामूहिक रूप से 3.46 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले सात वर्षों में बैंक धोखाधड़ी और घोटालों में हर दिन 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कई जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले जिनमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे लोग शामिल हैं, जो देश छोड़ भाग गए, को अब बैंकों के साथ समझौते के तहत राहत मिलेगी, उनमें कई भारी राइट-ऑफ (कर्ज बट्टे खाते) प्राप्त करने और फिर भी नए ऋण मांगने के लिए योग्य होंगे। आरबीआई की ओर से ऐसी दरियादिली कभी छोटी राशि के ऋण डिफाल्टरों के प्रति क्यों नहीं दिखाई गयी जिनमें किसान भी शामिल हैं। छोटे किसानों को जेल की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है, जबकि अमीर धोखेबाज व्यवसायियों को नियमित जमानत मिलती है, भारी कटौती होती है और उनका शानो-शौकत की जिंदगी चलती रहती है।

कई बार मैं सोचता हूं कि बैंकिंग सिस्टम अपने आप में ही बढ़ती असमानता का प्राथमिक कारण है। आखिरकार, यदि बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाले कर्जदारों के साथ बैंक नाजुकपन से पेश आयेंगे तो यह उसी गेम प्लान को उजागर करता है जो अमीर वर्ग को धन बटोरने में मददगार बनती है। बैंक उन्हें जनता के पैसे से छूट देकर उबारना जारी रखते हैं।

संरक्षण से ही जुड़ा है पृथ्वी का अस्तित्व

शशांक द्विवेदी

पिछले दिनों लोकसभा के मानसून सत्र में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 बिना किसी विरोध के पारित हो गया। असल में यह विधेयक 2002 के जैविक विविधता अधिनियम को संशोधित करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की सहायता के लिए लागू किया गया था। वर्ष 1992 में स्थापित सीबीडी यह मानता है कि देशों को अपने क्षेत्रों के भीतर अपनी जैविक विविधता को नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार है। इस विधेयक को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 16 दिसंबर, 2021 को संसद में पेश किया था। बाद में इसे 20 दिसंबर, 2021 को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था क्योंकि इसको लेकर यह चिंता जताई गई थी कि यह संशोधन उद्योगों के पक्ष में है और सीबीडी की भावना के विपरीत है। इसकी ध्यान से जांच करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने दो अगस्त, 2022 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि विधेयक पर कुछ छोटे बदलावों के बाद मंजूरी दी जा सकती है।

पूरी दुनिया की जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम आंधी, तूफान और बरसात से हजारों लोगों की जान जा रही है, साथ ही सभी ऋतु चक्रों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। सच्चाई यह है कि पर्यावरण या जैव विविधता संरक्षण सीधे-सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा मसला है। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा जारी 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1970 से 2018 के बीच 48 वर्षों के दौरान वन्य जीवों की आबादी में 69 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हैरान कर देने वाली बात है कि नदियों में पाए जाने वाले जीवों की करीब 83 फीसदी आबादी अब नहीं बची है। वर्ष 1970 के बाद फिशिंग 18 गुना बढ़ी है जिससे शार्क की आबादी में औसतन 71 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

दुनियाभर में पाए जाने वाले पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं की करीब एक-तिहाई प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक तरफ मानवीय जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, वहीं मानव अन्य जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को नष्ट कर उनकी जगह भी पसरता जा रहा है। वास्तव में जैव विविधता के संरक्षण के बिना विकास का कोई महत्व नहीं है। इस विधेयक में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देते हैं और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति का समर्थन करते हैं। वे इस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही औषधीय उत्पाद बनाने वाले चिकित्सकों और कंपनियों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकताओं को भी कम करते हैं। इसका अन्य उद्देश्य वन उपज का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना भी है। असल में यह संशोधन उन मुद्दों का समाधान नहीं करता, जिनका सामना भारत में जैव विविधता संरक्षण में करना पड़ता है। ऐसे में भारत को दिसंबर, 2022 में मॉन्ट्रियल में आयोजित सीबीडी के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में स्थापित नए संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया के पास अब सिर्फ सात साल बचे हैं।

एक सच्चाई यह भी है कि जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यक्रम होते हैं, उनमें विकासशील और विकसित देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर विवाद होता है। विकसित देश अधिक जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि विकासशील देश ही जैव विविधता दुनिया में गर्म होती जलवायु, कम होते जंगल, विलुप्त होते प्राणी, प्रदूषित होती नदियों, सभी को बचाने का काम करें। यहां तक कि इन कामों के लिए वे पर्याप्त आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जैव विविधता के लिए आधुनिक विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों के बीच संतुलित तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। जैव विविधता पर संकट इसका ही नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फिनिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2030 तक घने जंगलों का 60 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाएगा। वनों के कटान से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कार्बन अधिशोषण ही वनस्पतियों व प्राकृतिक रूप से स्थापित जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। मौसम के मिजाज में होने वाला परिवर्तन ऐसा ही एक खतरा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के पश्चिमी घाट के जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं।

जैव विविधता के लिए आधुनिक विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों के बीच संतुलित तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। वस्तुत: कोरोना का वैश्विक संकट इसका ही नतीजा था और अभी भी बरजरार है। जीव-जंतुओं और पौधों की लगभग 50 प्रजातियां रोजाना विलुप्त हो रही हैं, इसलिए आज पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाना जरूरी है। यह हमारी सोच में होना चाहिए कि जीव जंतुओं का महत्व हमसे कम नहीं है। कुल मिलाकर देश के प्राकृतिक संसाधनों का ईमानदारी से दोहन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ जनता की सकारात्मक भागीदारी की जरूरत है। जनता के बीच जागरूकता फैलानी होगी, तभी इसका संरक्षण हो पायेगा। जैव विविधता के संरक्षण का सवाल पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है।

आंवला

स्किन के लिए फायदेमंद

मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण खून को साफ करने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। जिससे आप बारिश के मौसम मे त्वचा से जुड़ी समस्या से राहत पा सकते हैं।

मानसून में ह्यूमिडिटी के कारण चकत्ते, मुंहासे और फंगल संक्रमण जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में अगर आप आंवला खाते हैं, तो इसमें

सांस संबंधी समस्या

मानसून में ह्यूमिडिटी के कारण चकत्ते, मुंहासे और फंगल संक्रमण जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में अगर आप आंवला खाते हैं, तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण खून को साफ करने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। जिससे आप बारिश के मौसम मे त्वचा से जुड़ी समस्या से राहत पा सकते हैं।

बारिश का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह मौसम चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दिलाता है। लेकिन मानसून सेहत संबंधी कई समस्याएं भी लेकर आता है। अगर आप इस मौसम में स्वस्थ रहेंगे, बारिश के मौसम में कमजोर इम्युनिटी, संक्रमण, अपच जैसी कई बीमारियों का सामाना करना पड़ता है। मानसून संबंधित इन समस्याओं को कम करने के लिए आपको अपने खानपान में बदलाव करना चाहिए। इस मौसम में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बेहद जरूरी है ताकि आप बीमारियों से बच सकें। इस मौसम में आंवला जरूर खाएं। आप इसे खाने में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आयुर्वेद में आंवला का इस्तेमाल सदियों से किया जाता है। इसका उपयोग जड़ी-बूटियों में भी किया जाता है।

इम्युनिटी बढ़ाने और स्किन एलर्जी कम करने में सहायक

डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद

मानसून के मौसम में लोग खाने का भरपूर मजा लेते हैं। इस मौसम में स्नैक्स और मिठाइयां ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए खाने की ये सारी चीजें सेहत पर भारी पड़ सकती है। इससे रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव होता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो आंवला आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसमें क्रोमियम होता है, जो इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य रखने में मदद करता है।

इम्युनिटी बूस्टर

मानसून के मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तेजी से फैलने लगते हैं। जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में सर्दी-खांसी और अन्य कई बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इम्युनिटी पर ध्यान दें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए आप अपनी डाइट में आंवला जरूर शामिल करें। यह विटामिन-सी का समृद्ध स्रोत है। जो बारिश के मौसम में आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है। जिससे आप सर्दी, फ्लू या अन्य संक्रमण से बच सकते हैं।

हंसना मना है

भोलापन तो देखिए, एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गयी। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो उसको देखकर बोला कि आपकी दो पत्नियां हैं क्या?

प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी तभी कलेक्टर साहब आ गये, मैडम जी पकड़ी गयीं, बहुत देर उठाने के बाद जब मैडम की नींद खुली तो मैडम कलेक्टर को देखते हुए बोली तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था, कलेक्टर साहब बेहोश।

एक आदमी वकील बन गया, उनको पहला केस मिला, मुलजिम- वकील साहब कोशिश करना उम्र कैद हो, फंसी ना हो, वकील-तुम चिंता मत करो, मैं हुं ना, पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आते हुए पत्रकार- क्या हुआ, वकील- बहुत मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो रिहा कर रहा था।

रमेश के पास रात को सांताक्लॉज आया और बोला- कोई विश मांगो, रमेश बोला- मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है कोई दूसरी बीवी दिलवा दो, सांताक्लॉज ने रमेश को बहुत मारा, फिर पता चला रमेश की बीवी ही सांताक्लॉज बन के आयी थी, सावधान रहे, सतर्क रहे?

कहानी | आलू, अंडा और कॉफी बीन्स

एक बार एक पुत्री ने अपने पिता से शिकायत करते हुए कहा की, मेरी जिंदगी बहुत दयनीय होती जा रही है, एक समस्या खत्म होने के बाद एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। जिंदगी में समस्याएं लगातार आ रही है, मैं क्या करूं? उसके पिता एक शेफ थे, इसलिए उसको रसोई में ले गये, तीन वर्तनों में पानी भर के उसे गैस पर रख दिया। जब तीनों का पानी उबलने लगा, तब उसने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी के बीज डाल दिए। और ऐसा करके उसकी बेटी और पिता दोनों उस क्रिया को देखने लगे। कुछ देर बाद पिता ने गैस बंद की और सभी को बारी-बारी से कटोरी में निकालना शुरू किया, फिर कॉफी को कप में निकला दिया। पिता ने पुत्री से पूछा तुमने क्या देखा, वो बोली आलू, अंडा और कॉफी। तब पिता के कहने पर पुत्री ने आलू को टच करके देखा, जो अब कोमल हो गया था, अंडा भी अब उबल चुका था। फिर पिता ने पुत्री से कॉफी को एक घूंट पीने के लिए कहा। पुत्री ने एक घूंट पी, स्वाद होने के कारण उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने पिता से इन सब का मतलब जानने की कोशिश की, तब पिता ने समझाया आलू, अंडा एवं कॉफी सभी को एक ही तरह की स्थिति मिली गर्म पानी लेकिन सभी की प्रतिक्रिया भिन्न थी। आलू के कठोर होने के बावजूद गर्म पानी से वो खुद ही कोमल हो गया। ऐसा ही कुछ अंडे के साथ हुआ, लेकिन जो कॉफी के बीज थे, यूनिक होने के कारण उसने पानी को ही परिवर्तित करके कुछ नया पदार्थ बना दिया। उसी प्रकार तुम हो जब समस्या तुम्हारे पास आई तो, आई हुई समस्या के प्रति तुम्हरी प्रतिक्रिया ही तुम्हें सफल बनाती है, या तो तुम खुद बदल जाओ या फिर परिस्थिति को बदलकर सफल हो जाओ दोनों ही तुम्हारे हाथ में है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष कोर्ट-कचहरी में अनुकूलता रहेगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। झंझटों में न पड़ें। उधार दिया धन मिलने से राहत हो सकती है।

वृषभ चोट, चोरी व विवाद से हानि संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। कुसंगति से हानि होगी। अपने काम से काम रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

मिथुन राजकीय बाधा दूर होकर लाभ होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। लाभ होगा। रुके हुए काम समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कर्क भूमि व भवन संबंधी कार्य लाभ देंगे। रोजगार मिलेगा। शत्रु भय रहेगा। निवेश व नौकरी लाभ देंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। कार्य के विस्तार की योजनाएं बनेंगी।

सिंह रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। विवाद न करें। सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभिवृद्धि होगी।

कन्या उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। शत्रु सक्रिय रहेंगे। शोक समाचार मिल सकता है। थकान महसूस होगी। व्यावसायिक चिंता रहेगी। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा।

तुला रोमांस में समय बीतेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

वृश्चिक अतिथियों का आवागमन रहेगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। स्वाभिमान बना रहेगा। नई योजनाओं की शुरुआत होगी। संतान की प्रगति संभव है।

धनु बेरोजगारी दूर होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। जोखिम न लें। क्रोध एवं उतेजना पर संयम रखें। सत्कार्य में रुचि बढ़ेगी।

मकर कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्ययवृद्धि होगी। तनाव रहेगा। अपरिचितों पर विश्वास न करें। प्रयास में आलस्य व विलंब नहीं करना चाहिए।

कुम्भ दिन प्रेमभरा गुजरेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें। प्रियजनों से पूरी मदद मिलेगी।

मीन नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। मान-सम्मान मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी।

फिर गर्दा उड़ाने को तैयार रजनीकांत

जेलर का दमदार ट्रेलर रिलीज

उड़ाने के लिए तैयार थलाइवा साउथ फिल्मों के थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत अपने अनोखे अंदाज से एक बार फिर गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म ऐलान के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। अब फिल्म के ट्रेलर ने इस बेसब्री को और बढ़ा दिया है।

जेलर के ट्रेलर में एक बार फिर रजनीकांत एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर के कवर पेज पर थलाइवा एक आम सिंपल नागरिक की तरह फॉर्मल लुक में यानी पैंट और व्हाइट शर्ट पहने दिख रहे हैं। यहां उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ है और इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं।

जबरदस्त है फिल्म का ट्रेलर

2 मिनट 15 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत में देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिस के ट्रक पर हमला कर दिया है, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। इस मामले पर एक बैठक दिखाई गई।

दूसरी ओर रजनीकांत एक फैमिली मैन के रूप में नजर आ रहे हैं। यहां डॉक्टर उनके परिवार को उनकी एक अलग तरह की बीमारी के बारे में भी बताता नजर आ रहा है। ट्रेलर में यह देखना काफी दिलचस्प है कि एक फैमिली मैन अगले ही पल दुश्मनों की हड्डियां तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं, जैकी श्रॉफ की झलक भी देखने को मिल रही है, जो काफी खौफनाक अंदाज में नजर आए हैं। इसके बाद शुरू होता है दरिंदगी का खेल, जहां अंधाधुन लोगों का खून बहाया जा रहा है। ट्रेलर में सभी कलाकारों की झलक देखने को मिली है और सभी अपने रोल्स में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। बता दें कि मेकर्स ने अपने वादे के मुताबिक, बुधवार की शाम को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसी के साथ फैंस की दीवानगी का ही ये आलम है कि ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा है।

10 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

जेलर में रजनीकांत और जैकी श्रॉफ के अलावा तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णनन, योगी बाबू और विनायक जैसे मशहूर साउथ कलाकारों को भी देखा जाने वाला है। वहीं, फिल्म में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल और कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार शिव राजकुमार को कैमियों में देखा जाने वाला है। फिल्म 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है।

बॉलीवुड | मन की बात

मेरे पार्टनर हर्षवर्ग को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है : कल्कि केकलां

कल्कि केकलां इस वक्त अपने उस बयान को लेकर चर्चा में हैं जिसमें बिना शादी मां बनने पर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। कल्कि अपने पार्टनर Guy Hershberg के साथ रिलेशनशिप में हैं और 7 फरवरी 2020 को उन्होंने बेटी Sappho को जन्म दिया। इसके बाद बना शादी के मां बनने को लेकर उनकी खूब आलोचनाएं हुईं। अब कल्कि ने उन आलोचकों को करारा जवाब दे डाला है। कल्कि ने कहा, उनकी पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप से शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके पार्टनर हर्षबर्ग को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पहले से तलाकशुदा हूं और यही वजह है कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हमने शादी न करने का फैसला काफी सोच-समझकर लिया है और हम साथ रह रहे हैं।

बताते चलें कि कल्कि अपने पार्टनर Guy Hershberg के साथ गोवा में रहती हैं। ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गोवा में रहने की असली वजह ये है कि वो चाहती हैं कि उनकी बेटी वैसी जगह पर रहे जहां चारों ओर हरियाली हो उन्होंने बताया था कि हर्षबर्ग के साथ पहली मुलाकात इजराइल टूर के दौरान हुई थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो कल्कि ये जवानी है दीवानी और जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही मेड इन हेवन सीजन 2 और गोल्डफिश में दिखाई देंगी। गोल्डफिश एक मां-बेटी की कहानी है जहां बेटी भारत वापस आती है जब उसकी मां डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से जूझने की शुरुआत पर होती हैं।

Kalki Koechlin

क्रिसैन परेरा ड्रग्स मामले में हुईं बेगुनाह साबित

बॉलीवुड | गपशप

क्रिसैन परेरा ड्रग्स मामले में बड़ी खबर आ रही है। दरअसल परेरा को बीती रात शारजाह जेल से रिहा किया गया और वो आज मुंबई पहुंच गई हैं। यूएई अधिकारियों ने उन्हें ड्रग मामले के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उनका नाम ट्रैवल ब्लैकलिस्ट से हटा लिया गया है। परेरा आज मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर से भी मुलाकात करेंगी।

बता दें की परेरा को फर्जी ड्रग्स केस में उनके जानने वाले पॉल एंथनी ने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए फंसाया था। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जांच की और एक्ट्रेस को बेगुनाह साबित किया। जिसके बाद परेरा क शारजाह जेल से रिहा किया गया। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) लखीमपुर गौतम ने परेरा के आने को कंफर्म किया और कहा कि क्रिसैन के साथ क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह 11.30 बजे मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी।

बता दें कि पिछले महीने, शारजाह के अधिकारियों ने परेरा फैमिली को इंफॉर्म किया था कि क्रिसैन का पासपोर्ट एक कमिटी को भेजा गया था जिसे उनकी भारत वापसी पर फैसला लेना था। कमिटी ट्रैवल ब्लैकलिस्ट से उनका नाम हटाने पर रिव्यू कर रही थी। वहीं शारजाह कोर्ट ने अप्रैल में डिप्लोमैटिक चैनल के माध्यम से भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर उसे क्लीन चिट दे दी थी कि उसे मामले में फंसाया गया था। शहर की अपराध शाखा ने ब्रोकर पॉल एंथोनी और उसके साथी राजेश भोभाटे उर्फ रवि और ड्रग तस्कर शांतिसिंह राजपूत को 1 अप्रैल को शारजाह में एक वेब सीरीज के लिए फर्जी ऑडिशन आयोजित करने, क्रिसैन परेरा पर ड्रग्स भेजने और रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इस नदी में पानी की जगह बहते हैं पत्थर वैज्ञानिक भी नहीं जान सके वजह

आपको दुनिया में बहने वाली विभिन्न नदियों के बारे में जानकारी होगी। कुछ नदियाँ विशाल हैं, जबकि कुछ नदियाँ छोटी हैं। हर नदी का अपना अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास और महत्व होता है। हालांकि, क्या आपको दुनिया की एक अनोखी पत्थरों से भरी नदी के बारे में जानकारी है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस नदी के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानेंगे, जहां पानी की जगह पत्थर ही पत्थर होते हैं। यह नदी अन्य नदियों से अलग है और इसकी लंबाई कई किलोमीटर तक फैली हुई है। दुनियाभर के देशों में बहुत-सी नदियां बहती हैं। भारत की बात करें, तो यहां प्रमुख नदियों की संख्या लगभग 200 है। इसके अलावा, देश के विभिन्न राज्यों में छोटी से लेकर बड़ी नदियों का प्रवाह होता है। अब तक आपने देखा होगा कि नदियों में पानी के साथ विभिन्न आकार के पत्थर देखने को मिलते हैं। लेकिन रूस में एक ऐसी नदी है जहां पानी के बजाय नदी में पत्थरों का प्रवाह होता है। यहां पर नदी में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं। यह अद्वितीय नदी रूस में स्टोन रिवर या स्टोन रन के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां नदी में पत्थरों का नदी में प्रवाह होने की वजह से उनका अधिकारिक नाम रखा गया है। इस नदी के आसपास देवदार के वृक्षों के घने जंगल भी हैं और इसके पास एक वन क्षेत्र है, जिसमें विविध प्राणियों की एक अद्वितीय जीवन-पद्धति है। इस अनोखी नदी की लंबाई लगभग छह किलोमीटर है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 20 मीटर तक है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी अधिक है। इस नदी में मौजूद पत्थरों का वजन 10 टन तक होता है और इन पत्थरों का आकार भी अलग-अलग होता है। इसलिए, लोग इस नदी को देखने के लिए विभिन्न भूभागों से यहां पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों ने इस नदी के बारे में अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ शोधार्थी विचार करते हैं कि करीब 10,000 साल पहले पर्वतों की ऊंचाइयों से टूटे ग्लेशियर के पत्थर पानी के साथ यहां बहकर जमा हो गए।

अजब-गजब | इस देश में शादी को लेकर अपनायी जाती है अजीब परंपरा

शादी की रात दुल्हन का हो जाता है अपहरण

दुनिया के हर देश और शहर में शादी के कई अलग-अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। कुछ परंपराएं बेहद अजीब होती हैं तो कुछ रिवाज बेहद खास होते हैं। भारत में शादी में जूते चुराने की रस्म बेहद चर्चित है, ठीक उसी तरह रोम में ऐसी रस्म का पालन किया जाता है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल, यहां की शादी में दुल्हन के साथ अजीब रिवाज का पालन किया जाता है। इटली की राजधानी रोम में होने वाली शादी में कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है। इनमें लड़का-लड़की के परिवार के लोग भी हिस्सा लेते हैं। शादी में कई तरह के अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जिन्हें खेलने में लोगों को आनंद आता है। यहां की शादी में पालन किए जाने वाले रीति रिवाज के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं रोम की शादी के अजीबोगरीब रिवाज के बारे में...

रोम में शादी की रात दुल्हन का अपहरण करने का रिवाज है। दूल्हे के दोस्त ही दुल्हन को अगवा करते हैं और दुल्हन भी खुशी-खुशी उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब दोस्तों को फिरौती नहीं दी जाती है, तब तक दुल्हन को दूल्हे के पास नहीं जाने दिया जाता है। रोम की शादियों में पालन किए जाने वाले इस रिवाज का नाम ब्राइड नैप्पिंग है। इसमें दूल्हे के सामने से ही दुल्हन को उठा लिया जाता है। अपहरण को असली दिखाने के लिए दूल्हे के दोस्त अपने पास हथियार भी रखते हैं। शादी में आए मेहमानों और दूल्हे के सामने से दुल्हन का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद फिर दुल्हन को छोड़ने के बदले फिरौती मांगी जाती है। फिरौती मिलने के बाद ही दुल्हन को छोड़ा जाता है।

क्या मांगते हैं फिरौती में

रिवाज में दूल्हे के दोस्त दुल्हन को छोड़ने के बदले फिरौती मांगते हैं। सबसे खास बात यह है कि फिरौती में अधिकतर शराब की बोतलें मांगी जाती हैं या सबके सामने दूल्हे को प्यार का इजहार करना होता है। दुल्हन डांस करते हुए दूल्हे के दोस्तों के साथ चली जाती है। इसके पीछे की वजह मौज-मस्ती करना होता है। दुनिया के कई देशों में दुल्हन को अगवा करने की प्रथा का पालन किया जाता है। कुछ देशों में दुल्हन को छोड़ने के बदले पैसे की भी डिमांड की जाती है। जब मांग पूरी नहीं होती है, तब तक दुल्हन को कैदकर रखा जाता है।

संघीय ढांचे पर आघात कर रही है भाजपा सरकार : ललन सिंह

» दिल्ली अध्यादेश पर बीजेपी पर भड़की जदयू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। दिल्ली वाले बिल के बहाने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। लोकलाज से लेकर संघीय ढांचे तक की दुहाई दी। मगर दिल्ली वाला बिल पास हो गया, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल के खिलाफ बोलते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जो आप लेकर आए हैं, वो संघीय ढांचे पर आघात है। लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है।

ललन सिंह ने नसीहत दी कि लोकतंत्र, लोकलाज से चलता है। बहस के दौरान राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान ललन सिंह काफी अग्रेसिव दिखे। काफी तीखा अटैक वो केंद्र सरकार पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे एमसीडी एक करके आपको क्या मिला? एमसीडी चुनाव में भी आप हार गए। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री को जो-जो पैरा सही लगा उन्होंने दिल्ली अध्यादेश को लेकर बोल दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को नहीं पढ़ा। ललन सिंह ने कहा कि यही लोकतंत्र है, जो आप चलाना चाहते हैं?

2024 में जनता आपका हिसाब कर देगी

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह इतने तैश में आ गए कि वो सत्तापक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि 2024 में जनता आपका हिसाब कर देगी। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है। 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं। उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटिशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही आप लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और बैकडोर से दिल्ली पर शासन करना चाहते हैं।

जिसके खिलाफ पार्टी बनाई उसी से कर लिया गठबंधन : शाह

अमित शाह की बारी आई तो उन्होंने इतिहास की याद दिला दी। अमित शाह ने कहा कि राजीव रंजन जी ने कहा था कि लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी लोकलाज तो आप मत ही बोलिए क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करनेवालों के साथ आप बैठे हैं। फिर गठबंधन किए हैं। लोकलाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जेडीयू का जन्म ही आरजेडी के विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है।

अवैध खनन के मामले की जांच करेगी एनजीटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अवैध खनन कराने की शिकायत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने शिकायत में लगाए गए आरोपों और तथ्यों की पड़ताल के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के जिलाधिकारी की संयुक्त जांच समिति बनाने के निर्देश दिया हैं।

एनजीटी ने संयुक्त समिति को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर तत्काल बैठक करे। साथ ही, जिन इलाकों में अवैध खनन की शिकायत की गई है, उनका स्थलीय निरीक्षण करे। साथ ही शिकायतकर्ता, स्थानीय प्रतिनिधियों आदि से संपर्क साधकर गहनता से पूरे मामले की पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपे। इस दौरान अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रकों के माध्यम से अवैध परिवहन के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की जांच भी की जाएगी। जांच समिति को सात नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

» सांसद बृजभूषण सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

"मेरा अवैध खनन से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के संचालन की बात असत्य, अपुष्ट और गुमराह करने वाली है। इस संबंध में गोंडा जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, खनन और पर्यावरण विभाग से सच्चाई पता करनी चाहिए। - **बृजभूषण शरण सिंह,** सांसद

जलकल विभाग : भुगतान न किए जाने पर कर्मियों में रोष

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विभिन्न मौकों पर काम पर बुलाए जाने के बाद भी जलकल विभाग द्वारा भुगतान न किए जाने पर वहां के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों के संगठन ने अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी देने पर भी आपत्ति जताई है।

कर्मियों ने बताया कि पं0-094 / सचिव / संघ दिनांक 31 जुलाई के माध्यम से संगठन के सूची माग पत्र का कार्यवृत्त 1अगस्त को जारी कर संगठन की उपलब्ध कराया गया है। जारी की गई कार्यवृत्त पूर्णता भ्रामक है साथ ही 28. जुलाई को मा महापौर के कार्यालय में जलकल प्रशासन एवं संगठन के बीच जो सहमती बनी थी यह कार्यवृत्त उसके भी विपरीत है। अत: संगठन निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराता है।

वार्ता में संगठन ने यह स्पष्ट किया था की चूंकि जलकल विभाग एक अति आवश्यक सेवा का विभाग है और समय-समय पर प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को त्योहारिक अवकाशों (जैसे-होली, दिपावली, ईद आदि) मे कार्य करने को बुलाया जा रहा है।

सबका हक मारना चाहती है भाजपा : कमलनाथ

» बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को बंद करने की कोशिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने नितीश सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है। कलनाथ ने कहा कि भाजपा सामाजिक हकमारी की प्रतीक है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भाजपा 'जातिगत सर्वेक्षण' को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर

वंचित, शोषित के लिए 'सामाजिक न्याय' ही नहीं बल्कि आने वाले समय में 'आर्थिक न्याय' का भी रास्ता खोल दिया है।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जब अपने अधिकारों के लिए मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये प्रभुत्ववादी सोच के गिनती के लोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली इस गिनती-गणना के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। जातीय जनगणना सबके हक़ की आनुपातिक हिस्सेदारी की राह खोलेगी और सच में लोकतंत्र की दिशा नीचे-से-ऊपर की ओर जाएगी। भाजपा की सामंती सोच ग़ैर-बराबरी और दमन की रही है, इसीलिए वो ग़रीब-कमज़ोर के हक़ को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। जनता जातीय जनगणना को रोकनेवाली भाजपा को अगले चुनाव में इस तरह बहिष्कृत करेगी कि मतगणना के दिन न तो उनके नेता दिखाई देंगे और न ही उनके प्रत्याशी। भाजपा सामाजिक हकमारी का प्रतीक है।

मप्र में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई

सिंगरौली। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। इस हमले में युवक गंभीर रुप से घायल हो गया है। उसे नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आदिवासी युवक की शिकायत पर मोरवा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में टीम जुट गई है।दरअसल सिंगरौली जिले के मोरवा इलाके में गुरुवार की शाम 6 बजे के करीब उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विधायक के बेटे ने एक आदिवासी युवक पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली युवक के हाथ मे लगी। बताया जा रहा है कि विधायक पुत्र का किसी से विवाद शुरू हुआ था। इसी बीच सूर्य प्रकाश खैरवार अपने एक साथी के साथ वहां बीच-बचाव करने पहुंच गए। इसी बीच कहासुनी के दौरान विवेकानंद ने अपनी पिस्टल से सूर्य प्रकाश के ऊपर फायर कर दिया। गोली सूर्य प्रकाश के एक हाथ में जा लगी।

फिर चूकीं सिंधू, ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर

» अमेरिका की बेवेन झांग से सीधे गेम में हारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

सिडनी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू आस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की बेवेन झांग से सीधे गेम में हारकर बाहर हो गई। पिछले कई टूर्नामेंटों से शुरूआती दौर में ही बाहर होने के कारण विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसकी सिंधू को दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी झांग ने 39 मिनट में 21-12, 21-17 से हरा दिया। पिछले दस मुकाबलों में सिंधू ने झांग को छह बार हराया है लेकिन चीनी मूल की इस अमेरिकी खिलाड़ी से आज पार नहीं पा सकी।

सिंधू ने हमवतन अष्मिता चालिहा और आकर्षि कश्यप को पहले दो दौर में हराया था लेकिन झांग से हार निराशाजनक रही। अब वह 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व चैम्पियनशिप खेलेंगी। विश्व चैम्पियनशिप 2019 विजेता सिंधू चोट से उबरने के बाद से खराब फॉर्म से गुजर रही है। वह इस साल 12 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंटों में से सात में जल्दी बाहर हो गई। साल की शुरूआत में उन्होंने कोरिया के पार्क ताए सांग से नाता तोड़कर कुछ समय साइ की कोच विधि चौधरी के साथ काम किया। अब उनके साथ नये कोच मोहम्मद हफीज हाशिम हैं जो 2003 आल इंग्लैंड चैम्पियन रह चुके हैं। भारतीयों में एच एस प्रणय का सामना इंडोनेशिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त एंथोनी जिंटिंग से होगा जबकि 2021 विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत की टक्कर हमवतन प्रियांशु राजावत से होगी।

दक्षिण क्षेत्र बना नौवीं बार देवधर ट्रॉफी चैंपियन

नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज रोहन कनूमल के तूफानी शतक से शानदार आगाज करने वाले दक्षिण क्षेत्र ने गुरुवार को यहां फाइनल में पूर्व क्षेत्र को 45 रन से हराकर नौवीं बार देवधर ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। रोहन ने 75 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्होंने कप्तान मयंक अग्रवाल (83 गेंदों पर 63 रन)के साथ पहले विकेट के लिए 181 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखी। नारायण जगदीशन ने भी 60 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाले दक्षिण क्षेत्र में आठ विकेट पर 328 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में पूर्व क्षेत्र की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर तीन विकेट पर 14 रन था।

अंतर-सेवा संगठन विधेयक लोकसभा में पास, राज्यसभा में भारी हंगामा

मणिपुर व राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर तीखी बहस सरकार बोली चर्चा से भाग रहा विपक्ष

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के सदस्य मणिपुर हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा करने की अपनी मांगों पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ते देख सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (7 अगस्त) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं लोकसभा में भी नोकझोंक चलती रही और इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया।

बिल को निचले सदन से मंजूरी भी मिल गई। विधेयक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

मानसून सत्र में सदन चलाने को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी

मानसून सत्र में अब तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बगैर किसी रुकावट के नहीं चल सकी है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों ही सदन में मणिपुर हिंसा का मामला विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। मानसून सत्र में आगे की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक विशेष रणनीति पर काम कर रही है, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर एक बैठक भी की है। सूत्रों के अनुसार व्हिप के साथ हुई बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों सदनों में पार्टी के सांसदों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, ध्यान रखें की एक भी सांसद छूटना नहीं चाहिए. बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के स्पीकर को मिलाकर कुल 301 सांसद हैं जबकि राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की कुल संख्या 92 है, हालांकि बीजेडी, वायएसआरसीपी, टीडीपी ने दोनों मुद्दों पर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है।

केजरीवाल सरकार के खिलाफ नहीं है बिल : रामदास अठावले

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशानिर्देश दिए थे उसके दायरे में रहकर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया है। लोकसभा में बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी बिल पास होगा। ये बिल केजरीवाल सरकार के खिलाफ नहीं है। पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार भी रही है। तब भी पूरा अधिकार केंद्र को था, केजरीवाल जो विषय उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है।

राजस्थान पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी

सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में नियम 176 के तहत राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग की। ट्रेजरी बेंच के सांसदों ने सदन में राजस्थान पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की।

विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए

बीआरएस सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सेवा विधेयक को वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा पर बयान देने की मांग की।

विपक्ष के पास तथ्य नहीं है : ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद जब इनकी जगहंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर सब आए पर न तर्क था न कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। अब तक जो विपक्ष ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है।

चीन सीमा विवाद और मणिपुर मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मनिकम टैगोर ने चीन के साथ सीमा स्थिति और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इसके अलावा राजद सांसद मनोज झा और आप सांसद राघव चंदा ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।

फोटो: सुमित कुमार

जवानों ने बचाई बेजुबां की जान

हजरतगंज चौराहे पर पेड़ के ऊपर मांझे में फंसे बेजुबां कौवे को फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन द्वारा जवानों ने पेड़ से उतारकर उसकी जान बचायी।

सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट का झटका

» दिल्ली शराब घोटाला मामला: सुनवाई 4 सितंबर तक टली

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिली है, कोर्ट ने मामला 4 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने सुनवाई की। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई, वह पीठ में दर्द, चलने-फिरने में असमर्थ हैं, कोर्ट ने कहा है कि मरीज इंडोर है या आउटडोर. सिंघवी आउट डोर है, इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत अर्जी खारिज नहीं कर रहे, ये बीमारी कंट्रोल करने से नियंत्रण में रहती है, उन्हें एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में ले जाने में हमें कोई दिक्क त नहीं है, क्योंकि बीमारी और उसकी गंभीरता से हम इंकार नहीं कर रहे, लेकिन ये जमानत का आधार नहीं हो सकता।

सीबीआई ने जमानत का किया विरोध

हालांकि सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और इसको लेकर हलफनामा भी दाखिल किया है। दाखिल हलफनामे में कहा है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं, सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनका इलाज 23 साल से चल रहा है। एससी ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी जा सके।

उत्तराखंड में भूस्खलन 13 लोग हुए लापता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कर्णप्रयाग। मूसलाधार बारिश के कारण उत्तराखंड ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे कमेड़ा में बंद है। 13 लोगों के लापता हाने की खबरे आ रही हैं। कमेड़ा में दलदल में वाहन फंसा है और सुबह से रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली सहित कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बदरीनाथ व गोपेश्पर आने-जाने वाले करीब 150 वाहन फंसे हैं।

जबकि कर्णप्रयाग में उमा देवी तिराहे के पास एनएच का पुश्ता टूटने से सड़क पर मलबा और पत्थर गिरे हैं। ऋषिकेश व बदरीनाथ की ओर जाने वाले 100 से अधिक वाहन फंसे हैं। स्थानीय लोगों को कहना है कि कर्णप्रयाग में लगातार एनएच का पुश्ता टूट रहा है। इससे वाहनों सहित स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे पर मल्यापौड़ में गिरा मलबा हटा दिया गया है, जबकि हरमनी में यह हाईवे अभी भी बाधित है।

केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को अदालती नोटिस

» इंडिया गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कई राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो कि निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और रणनीतिक कदम है। यह चिंगारी जो राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है जो अंतत: राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी।

याची का आरोप- राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से कर रहे इस्तेमाल

याचिका में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर रहे हैं जो न केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए कारक के रूप में कार्य करेगा। याचिका में कहा गया कि इन राजनीतिक दलों के कृत्य से आगामी 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।